हस्तक्षेप

370 के बाद कश्मीर

बदलता विमर्श, बदलते आयाम

www.samaylive.com

राष्ट्रीय सहारा

नई दिल्ली। शनिवार ● 31 अगस्त ● 2019

hastkshep.rsahara@gmail.com

कश्मीर पर किस असमंजस में है कांग्रेस?

■ प्रमोद जोशी

वरिष्ठ पत्रकार

अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी करने का आदेश पास होने के 23 दिन बाद राहुल गांधी ने कश्मीर के सवाल पर एक महत्वपूर्ण ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, 'सरकार के साथ हमारे कई मुद्दों को लेकर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह साफ है कि कश्मीर हमारा आंतरिक मामला है। पाकिस्तान वहां हिंसा फैलाने के लिए आतंकियों का समर्थन कर रहा है। इसमें पाकिस्तान समेत किसी भी देश के दखल की जरूरत नहीं है।'

राहुल गांधी ने ऐसा बयान क्यों जारी किया, इस वक्त क्यों किया और अभी तक क्यों नहीं किया था। ऐसे कई सवाल मन में आते हैं। राहुल के बयान के पीछे निश्चित रूप से पाकिस्तान सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र को लिखे गए एक खत का मजमून है। इसमें पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि कश्मीर में हालात सामान्य होने के भारत के दावे झूठे हैं। इन दावों के समर्थन में राहुल गांधी के एक बयान का उल्लेख किया गया है, जिसमें राहुल ने माना है कि 'कश्मीर में लोग मर रहे हैं' और वहां हालात सामान्य नहीं है।

बड़ी देर कर दी

'हालात सामान्य नहीं हैं' तक बात मामूली है, क्योंकि देश में काफी लोग मान रहे हैं कि कश्मीर में हालात सामान्य नहीं है। सरकार भी एक सीमा तक यह बात मानती है। पर 'कश्मीर में लोग मर रहे हैं' कहने पर मतलब कुछ और निकलता है। तथ्य यह है कश्मीर में किसी आंदोलनकारी के मरने की खबर अभी तक नहीं है। पाकिस्तानी चिट्ठी में नाम आने से राहुल गांधी का सारा राजनीतिक गणित उलट गया है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट करने में देर कर दी है। कहना मुश्किल है कि आने वाले दिनों में उनकी राजनीति की दिशा क्या होगी।

राहुल ने ही नहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कहा, हमें ऐसी रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान सरकार संयुक्त राष्ट्र में जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर अपने झूठ को सच साबित करने के लिए राहुल गांधी का नाम ले रही है। पाकिस्तान राहुल के नाम पर गलत संदेश फैला रहा है। इसी कारण राहुल ने साफ कर दिया है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न अंग है और हमेशा बने रहेंगे। सवाल है कि क्या राहुल गांधी को यह सफाई देने की जरूरत ही क्या थी?

बोलना पहले था

यह तो कांग्रेस का हमेशा से दृष्टिकोण रहा है। आज किसी को क्यों लगता है कि यह दृष्टिकोण अब नहीं है? कांग्रेस को इस सवाल पर जिस गहराई से विचार करना चाहिए, वह नहीं किया गया है। पार्टी ने कश्मीर समस्या को पिछले पांच साल की राजनीति में समेट लिया है और जिन मसलों पर उसे अपने परंपरागत दृष्टिकोण पर दृढ़ रहने की जरूरत थी, उन्हें उसने बिसरा दिया है। गत 6 अगस्त को लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का मसला 1948 से संयुक्त राष्ट्र (यूएन) देख रहा है और ऐसे में क्या यह मामला अंदरूनी हो सकता है? पार्टी की ओर से किसी ने नहीं कहा कि यह गलत बात है। बाद में चौधरी ने अपने बयान की सफाई दी, पर वे भारी गलती कर चुके थे। इस गलती को पार्टी ने तभी महसूस किया, जब पाकिस्तान ने अपने पत्र में राहुल गांधी का नाम लिख दिया। जबकि जरूरत उसके पहले थी। पार्टी को अब भी यह बात समझ में नहीं आ रही है कि उसके नैरेटिव में क्या खामी है, तो यकीनन उसका बेड़ा गर्क होने में अब ज्यादा देर नहीं है।

कश्मीरी आंदोलन

अनुच्छेद 370 को लेकर पार्टी का दृष्टिकोण समझ में आता है, नागरिक अधिकारों को लेकर भी उसकी धारणा सही है। पर कश्मीरी अलगाववाद के बारे में उसे अपनी नजरिए को स्पष्ट करना होगा। एक बात साफ है कि इस्लामिक स्टेट, अलकायदा, लश्करे तैयबा, जैशे मोहम्मद, हिज्बुल मुजाहिदीन से लेकर हुर्रियत कांफ्रेंस सबका एक नारा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या 'ला इलाहा लिल्लल्लाह।' वह न तो कश्मीरियत का और न धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की स्थापना का आंदोलन है।

कांग्रेस को लगता है कि भारत के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए कश्मीरी आंदोलनकारियों का समर्थन जरूरी है, तो यह भी गलतफहमी है। भारतीय मुसलमानों के हित में यह बात उसी हद तक जाएगी, जिस हद तक कश्मीर में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की स्थापना के लिए आंदोलन होगा। भारत की जमीन पर एक और सांप्रदायिक विभाजन की कल्पना ही भयावह है और इसके दुष्परिणामों पर शायद कांग्रेस ने विचार नहीं किया है। उसकी इस नासमझी का फायदा बीजेपी ने लगातार उठाया है।

राष्ट्रहित सर्वोपरि

कश्मीर में नागरिक स्वतंत्रताओं पर लगी पाबंदियों का विरोध करने में कोई गलती नहीं है, पर पाबंदियां हटने का मतलब यह नहीं है कि पत्थर मार आंदोलन फिर से शुरू हो जाए। भारतीय सेना पर पत्थर मारने का समर्थन नहीं किया जा सकता है। यह आत्मघाती राजनीति है और कांग्रेस को इसे समझना चाहिए। कश्मीरी पत्थरबाज अनुच्छेद 370 के लिए नहीं लड़ रहे हैं। और न उनका आंदोलन बीजेपी के खिलाफ है। उन्होंने तो सन 2010 में पत्थर बरसाना शुरू किया था। पत्थरबाज भारत में रहते हुए स्वायत्तता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। ऐसा होता तो उनके हाथों में पाकिस्तानी झंडे नहीं होते, जम्मू-कश्मीर का झंडा होता। यह बात नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के नेताओं को भी समझनी होगी, जो कश्मीर के भारत में विलय के समर्थक है। सच यह है कि आज भी कश्मीर में बड़ी संख्या में लोग विलय को स्वीकार करते हैं और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, पर पीडीपी और नेकां ने कट्टरपंथियों का मुकाबला करने के बजाय उनके सामने घुटने टेके हैं।

कांग्रेस स्पष्ट नहीं

कश्मीर को लेकर पार्टी का दृष्टिकोण तबसे बदला, जब कश्मीर विधानसभा चुनाव के बाद वहां बीजेपी और पीडीपी की सरकार बनी। पर क्या इससे कश्मीर को लेकर पूरा नजरिया बदल जाना चाहिए? क्या 2014 के बाद कश्मीरी आंदोलन के पीछे पाकिस्तान का हाथ नहीं रहा? कश्मीर भारतीय राष्ट्र-राज्य की समस्या है, केवल बीजेपी और कांग्रेसी राजनीति की समस्या नहीं। कम से कम राष्ट्रीय सुरक्षा और अखंडता के प्रश्नों पर पार्टी का रुख गंभीर विचार-विमर्श के बाद ही तय होना चाहिए। कश्मीर के सवाल पर पार्टी थोड़ी देर के लिए बीजेपी के साथ खड़ी हो जाएगी, तो इससे उसका नुकसान नहीं होगा, बल्कि लाभ मिलेगा। उसे बहुसंख्यक जनता की भावना को भी समझना चाहिए। जनता को नरेंद्र मोदी अपने जैसे क्यों लगते हैं? पार्टी के भीतर से निकल रहे दो प्रकार के स्वरों का संदेश क्या है? क्या यह अच्छे स्वास्थ्य का लक्षण है? मतभेद होना कोई गलत बात तो नहीं। पर कांग्रेस की परम्परा, नेतृत्व शैली और आंतरिक संरचना को देखते हुए यह अटपटा है। दरअसल समस्या उस नैरेटिव की है, जिसे कांग्रेस स्पष्ट नहीं कर पा रही है।

अंतर्विरोधी स्वर

जैसे-जैसे कांग्रेस पार्टी की कमजोरियां सामने आ रही हैं, वैसे-वैसे उसके भीतर से अंतर्विरोधी स्वर भी उठ रहे हैं। अगस्त के पहले हफ्ते में अनुच्छेद 370 को लेकर यह बात खुलकर सामने आई थी। नरेंद्र मोदी के प्रति 'नफरत' को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने जयराम रमेश और अभिषेक मनु सिंघवी की बातों का समर्थन करके पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण रणनीति पर सवालिया निशान लगाया है। क्या यह राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणियां हैं? पार्टी में कोई भी नहीं मानेगा कि ये बयान सीधे-सीधे राहुल गांधी की रीति-नीति के विरुद्ध हैं। सवाल है कि ये नेता तब किसके बारे में बोल रहे हैं? पार्टी की दिशा कौन तय कर रहा है? इससे ज्यादा साफ शब्दों में कोई बात नहीं कही जा सकती और जब राहुल गांधी ने कश्मीर पर सफाई पेश की, तब यह बात साफ हो गई कि कहीं न कहीं पर पार्टी में गहरा सोच-विचार नहीं है। ■

> कांग्रेस को लगता है कि भारत के मुसलमानों का दिल जीतने के लिए कश्मीरी आंदोलनकारियों का समर्थन जरूरी है, तो यह भी गलतफहमी है। भारतीय मुसलमानों के हित में यह बात उसी हद तक जाएगी, जिस हद तक कश्मीर में धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था की स्थापना के लिए आंदोलन होगा। भारत की जमीन पर एक और सांप्रदायिक विभाजन की कल्पना ही भयावह है और इसके दुष्परिणामों पर शायद कांग्रेस ने विचार नहीं किया है। उसकी इस नासमझी का फायदा बीजेपी ने लगातार उठाया है

इलस्ट्रेशन : जे.पी. त्रिपाठी

नया भारत, नया जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

■ प्रो. हरि ओम

पूर्व विभागाध्यक्ष, राजनीति विज्ञान विभाग, जम्मू विश्वविद्यालय

गए वो दिन जब गंदे मंसूबे पाले देश तथा कश्मीर और अन्य जगहों में उनके पैसों पर पल रहे एजेंट भारत राष्ट्र को रक्तरंजित करते थे, और नई दिल्ली बेहद दबी-दबी सी प्रतिक्रिया ही दे पाती थी। लेकिन आज भारत ने एक संप्रभु देश की भांति व्यवहार करना आरंभ कर दिया है, प्रतिक्रिया जताने लगा है। जवाब देता है, ऐसा जवाब जिसका कोई मतलब होता है, नतीजा निकलता है। पाकिस्तान को लेकर भारत की विदेश नीति में खासा बदलाव आया है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हालात बदले

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हालात बदले हैं, और पूरी तरह बदले हैं। नेहरू की नीति अप्रासंगिक हो गई है, खारिज हो चुकी है। विभाजनकारी अनुच्छेद 370 को डस्टबिन में डाल दिया गया है। भेदभाव करने वाला अनुच्छेद 35ए बीते कल की बात हो गया है। इन्हीं दोनों अनुच्छेदों के बल पर पृथकतावादी और कथित मुख्यधारा के कश्मीरी नेता बीते सात दशकों से राज्य की राजनीति को कमजोर किए हुए थे। कश्मीरी मुस्लिमों में जहर भरते थे कि वे भिन्न नस्ल हैं। भारत संघ में रहते हुए भी उनका विशेष दरजा है, अलग हैसियत है। दोनों अनुच्छेदों के चलते पाकिस्तान और कश्मीर में भारत-विरोधी ताकतों ने चौबीसों घंटे सातों दिन मुहिम चला रखी थी कि जम्मू-कश्मीर विवादास्पद क्षेत्र है। विश्व समुदाय को जताते थे कि जम्मू-कश्मीर भारत, पाकिस्तान और कश्मीरी मुस्लिमों के बीच विवादास्पद मसला है।

इन अनुच्छेदों के अलावा नागरिक सचिवालय, राज्य विधानसभा, पुलिस, कानून एवं राजस्व विभागों का इस्तेमाल करते हुए अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार ने जम्मू तथा लद्दाख को कश्मीर की कॉलोनियों में तब्दील कर डाला था। वहां के लोगों को तमाम तरह से निष्प्रभावी बना दिया था। अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों ने जम्मू और लद्दाख की जनसांख्यिकी को ही बदल डालने की कोशिश की ताकि वहां भी कश्मीर जैसी स्थिति बन जाए। ऐसी स्थिति जिससे भारत को तोड़ने का नापाक मंसूबा पूरा किया जा सके। हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों के बीच भय का माहौल पैदा कर दिया था। इन्हीं अनुच्छेदों के बल पर भारत-विरोधी ताकतों ने 1990 तक कश्मीर को शत-प्रतिशत मुस्लिम आबादी वाला इलाका बना दिया। मोदी सरकार ने इन अनुच्छेदों को खत्म करके अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवारों पर कड़ा प्रहार किया है। पांच अगस्त को बड़े नाटकीय तरीके से एक हस्ताक्षर भर से गंदे मंसूबे पाले लोगों के बुरे दिन आरंभ हो गए।

बहत्तर वर्षों में पहली बार

इतना ही नहीं, जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। बहत्तर वर्षों में पहली बार हुआ है कि राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख-में विभाजित कर दिया गया। अब तीनों क्षेत्रों पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होगा। वृहत स्वायत्तता, जो करीब-करीब संप्रभुता के निकट की अवधारणा है, के फारूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत तमाम हामी कश्मीर तक में अप्रासंगिक हो गए हैं। जम्मू और लद्दाख की तो बात ही छोड़िए जहां उनकी सुनी तक नहीं जाती थी। अब्दुल्ला पिता-पुत्र को नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती समेत तमाम वे लोग, जो पाकिस्तान, स्वशासन या भारत में सीमित विलयन, जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान के संयुक्त नियंत्रण, दोहरी मुद्रा, असैन्यीकरण, नरम सीमा, पोरस लाइन ऑफ कंट्रोल तथा साझी संप्रभुता के हामी रहे हैं, भी अप्रासंगिक हो गए हैं। महबूबा को भी नजरबंद कर दिया गया है। कश्मीर में कांग्रेस, माकपा, पिपुल्स कांफ्रेंस तथा पिपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट जैसी अन्य राजनीतिक पार्टियों की कहानी भी कोई जुदा नहीं है। इन राजनीतिक दलों के ज्यादातर नेता भी अप्रासंगिक हो गए हैं। अधिकांश को नजरबंद किया गया है।

कश्मीर घाटी में इन तमाम नेताओं और राजनीतिक संगठनों का कोई जमाल नहीं रहा। सबसे बड़ा झटका तो यह लगा है कि इन्हें नजरबंद किए जाने के बाद घाटी के दस जिलों में पत्ता भी नहीं हिला। कोई हिंसा प्रदर्शन नहीं हुआ। मोदी सरकार काम करने में विश्वास करती है, और विरोध प्रदर्शन करने वालों को पता है कि ऐसा करने का नतीजा क्या हो सकता है। केंद्रीय नेतृत्व और जम्मू-कश्मीर के गर्वनर एसपी मलिक ने कई बार स्पष्ट किया है कि कश्मीर और केंद्र में आसीन सत्ताधारी उनकी जरूरतों को पूरा करेंगे। राज्य-विरोधी तत्वों को नहीं बख्शेंगे। सबसे अच्छी बात तो यह रही कि कश्मीर में किसी मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम धार्मिक स्थानों या मस्जिदों से कोई बयान जारी नहीं हुआ जिसमें नई कश्मीर नीति का विरोध किया गया हो या मोदी सरकार की आलोचना की गई हो।

जम्मू और लद्दाख में तो पांच अगस्त के बाद से ही उत्सव जैसा माहौल है। वहां लोगों को लगता है कि अब उनकी आवाज को पुरजोर तरीके सुना जाएगा। उन्हें राजनीतिक-आर्थिक प्रक्रियाओं का हिस्सा बनाया जाएगा। बहरहाल, कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने जम्मू, कश्मीर और लद्दाख में समूचा विमर्श ही बदल दिया है। अपने फैसले से स्पष्ट कर दिया है कि जम्मू, कश्मीर और लद्दाख विवादास्पद क्षेत्र नहीं हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अब एक ही मसला अनसुलझा है-पीओजेके और गिलगित-बाल्टिस्तान का राजनीतिक भविष्य।

विश्व के अधिकांश देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, उनकी पाकिस्तान नीति और सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण जम्मू-कश्मीर तथा लद्दाख संबंधी नीति का समर्थन कर रहे हैं। समूचा विमर्श ही बदल गया है। अब नई दिल्ली पाकिस्तान और उस जैसी गंदी मंशा पाले देशों को दोटूक कहती है कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के बाकायदा हिस्से हैं, और वह एकसूत्री एजेंडा को लेकर संकल्पबद्ध है कि 1947-48 के बाद से जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने गैर-कानूनी कब्जा कर रखा है, उसे हर हाल में वापस हासिल करेगी। गौरतलब है कि पाक-अधिकृत जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) तथा गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान अवैध रूप से काबिज है।

प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक स्वर में बोल रहे हैं। वैश्विक आतंक का केंद्र बने पाकिस्तान को चेताने में कसर नहीं छोड़ रहे। चेता रहे हैं कि पाकिस्तान रवैया सुधारे वरना उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सच कहें तो भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि भारत जरूरत पड़ने पर बालाकोट जैसी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा। अपने संप्रभु हितों की रक्षा के लिए संकल्पबद्ध है। अपने क्षेत्र को नुकसान नहीं पहुंचने देगा। वास्तव में, यह नया भारत है, स्वाभिमानी देशों की कतार में शामिल। ■

> बहत्तर वर्षों में पहली बार हुआ है कि जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र-शासित प्रदेशों-जम्मू-कश्मीर और लद्दाख-में विभाजित कर दिया गया। अब तीनों क्षेत्रों पर सीधे केंद्र सरकार का शासन होगा। वृहत स्वायत्तता, जो करीब-करीब संप्रभुता के निकट की अवधारणा है, के फारूख अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला समेत तमाम हामी कश्मीर तक में अप्रासंगिक हो गए हैं। जम्मू और लद्दाख की तो बात ही छोड़िए जहां उनकी सुनी तक नहीं जाती थी। अब्दुल्ला पिता-पुत्र को नजरबंद कर दिया गया है। महबूबा मुफ्ती समेत तमाम वे लोग, जो पाकिस्तान, स्व-शासन या भारत में सीमित विलयन, जम्मू-कश्मीर में भारत-पाकिस्तान के संयुक्त नियंत्रण, दोहरी मुद्रा, असैन्यीकरण, नरम सीमा, पोरस लाइन ऑफ कंट्रोल तथा साझी संप्रभुता के हामी रहे हैं, भी अप्रासंगिक हो गए हैं

पेज 2 फैजान मुस्तफा । राजेन्द्र शर्मा। अनिल चमड़िया

पेज 3 अरविन्द मोहन । शंकर शरण। अग्निशेखर

पेज 4 अवधेश कुमार । विजय शंकर सिंह । दीपिका भान